सत्यमेव जयते

भारत सरकार

बजट की

मुख्य

विशेषताएं

2024-2025

फरवरी, 2024

वित्त मंत्रालय

बजट प्रभाग

2047 तक विकसित भारत

परिकल्पना: प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना और सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत

विकास मंत्र

सबका साथ,
सबका विकास

सभी का व्यापक विकास

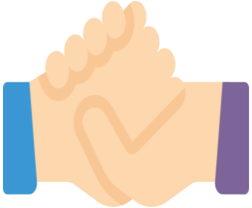

सबका साथ,
सबका विकास,
सबका विश्वास

'सबका प्रयास' के समर्थन से
जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता

विकसित भारत
@ 2047

जन-केंद्रित समावेशी विकास

सभी प्रकार की अवसंरचना-भौतिक, डिजिटल और सोशल का ठोस विकास

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई)-औपचारिकीकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला

जीएसटी द्वारा कर आधार को गहनता और विस्तार की प्राप्ति हुई

सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र से बचत, ऋण और निवेश वापस पटरी पर लौटे

जीआईएफटी आईएफएससी- अर्थव्यवस्था में वैश्विक पूंजी और वित्तीय सेवाओं का मजबूत द्वार

मुद्रास्फीति का सक्रिय प्रबंधन

देश के सभी भाग आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं

डॉलर के संदर्भ में भारत और विश्व की जीडीपी की विकास दर

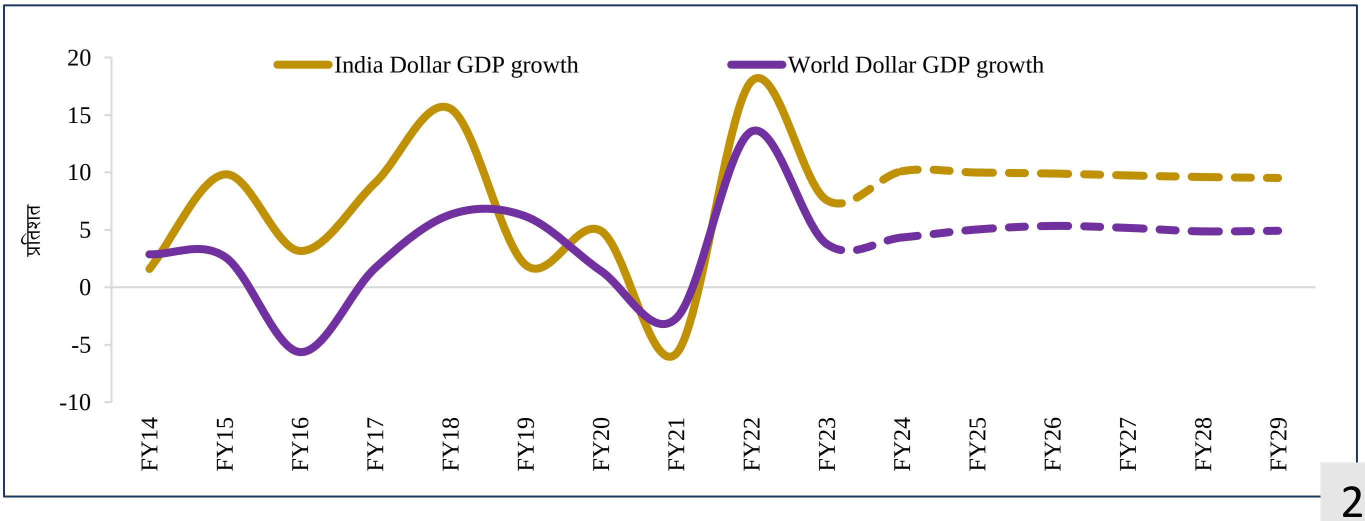

प्रमुख क्षेत्र (1/2)

गरीब कल्याण, देश का कल्याण

डीबीटी से ₹2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है

25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए

पीएम-स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहडी पटरी वालों को ऋण सहायता

गरीबों की संख्या के प्रतिशत में कमी

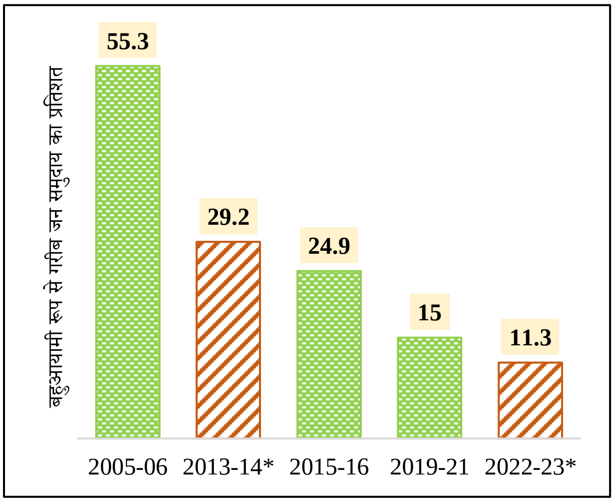

*अनुमान

युवाओं का सशक्तीकरण

1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ

युवाओं की उद्यमी बनने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए-पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए

पीएम-श्री बजट आवंटन में बढ़ोत्तरी

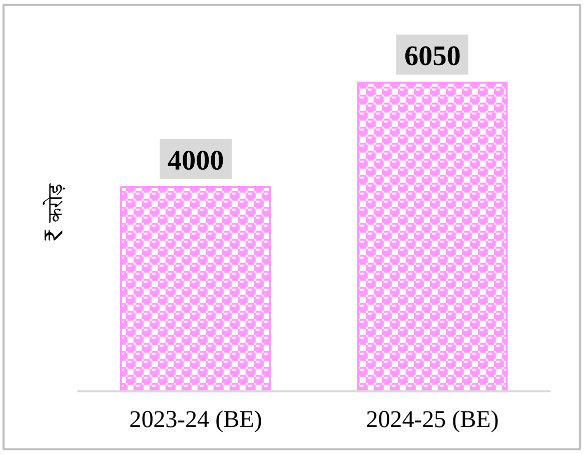

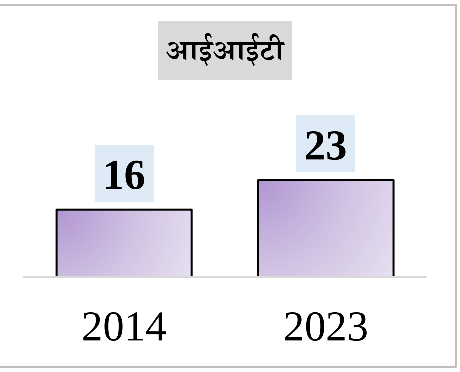

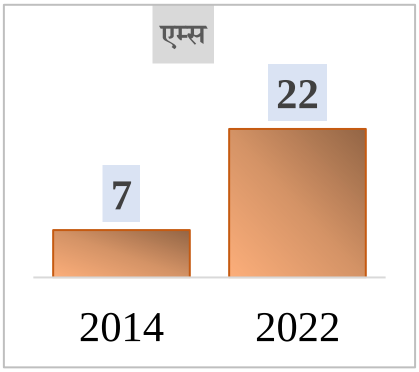

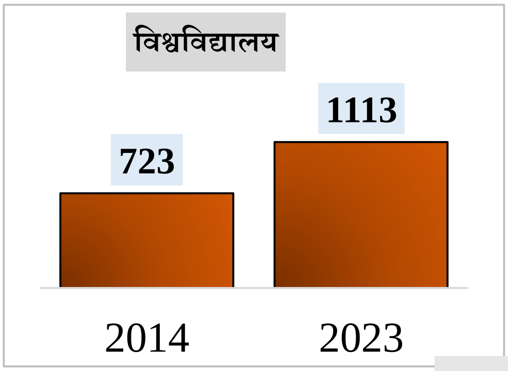

प्रमुख क्षेत्र (2/2)

किसान-*अन्नदाता* का कल्याण

पीएम-किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा

₹ 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम का समर्थन करने वाले ई-एनएएम के तहत 1,361 मंडियों का समेकन

गेहूं और चावल की खरीद का बढ़ना

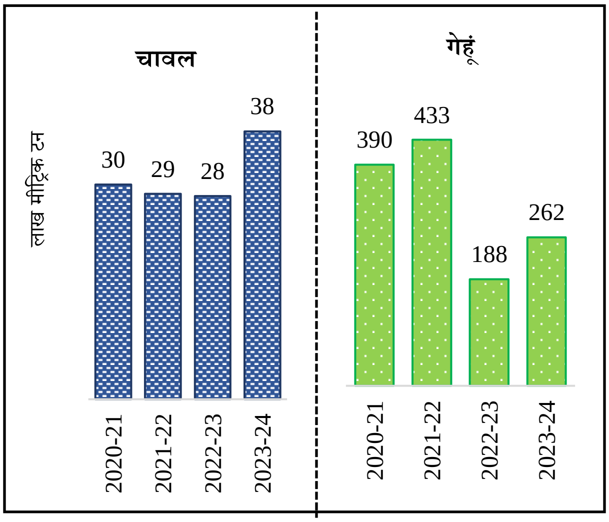

नारी शक्ति

महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण संवितरित किए गए

10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28 प्रतिशत की वृद्धि

स्टेम पाठ्यक्रमों में महिलाओं का 43 प्रतिशत नामांकन

83 लाख स्व-सहायता समूहों की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं

श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना

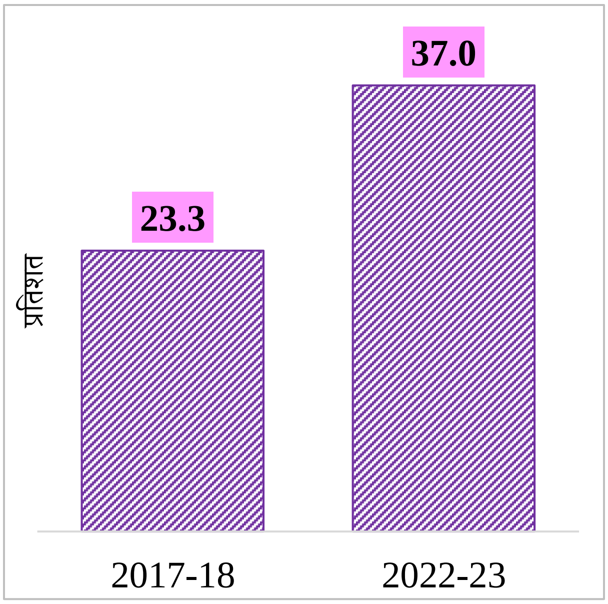

अमृत काल के लिए कार्यनीति (1/5)

संधारणीय विकास

वर्ष 2070 तक 'निवल शून्य' की प्रतिबद्धता को पूरा करना

- पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन
- कोयला, गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता की स्थापना
- सीएनजी, पीएनजी और संपीड़ित वायोगैस का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण
- बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता

छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना – प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली पाने में 1 करोड़ परिवारों की सहायता

- सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों को अपनाना
- ई-वाहन के विनिर्माण और चार्जिंग द्वारा ई-वाहन ईकोसिस्टम को मजबूत बनाना

पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए बायो-मैनुफैक्चरिंग और बायो-फाउंड्री की नई योजना शुरू की जानी है

गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के प्रतिशत में वृद्धि

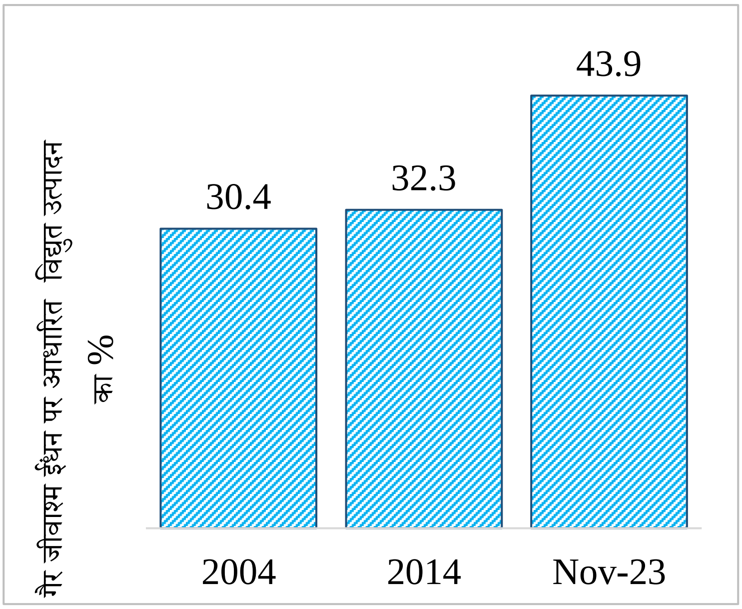

- पीएमयूवाई के तहत >10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए
- उजाला के तहत 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब, 72.2 लाख एलईडी ट्यूब लाइट और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया
- एसएनएलपी के तहत 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गईं

अमृत काल के लिए कार्यनीति (2/5)

अवसंरचना और निवेश

लॉजिस्टिक कार्यकुशलता बढ़ाने तथा लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 3 बड़े रेलवे कोरिडोर कार्यक्रमों को लागू करना

द्विपक्षीय निवेश समझौते के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना

उड़ान योजना के अंतर्गत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार तथा नए हवाई अड्डे का व्यापक विकास

मेट्रो रेल और नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तनों को बढ़ावा देना

पूंजीगत व्यय में वृद्धि

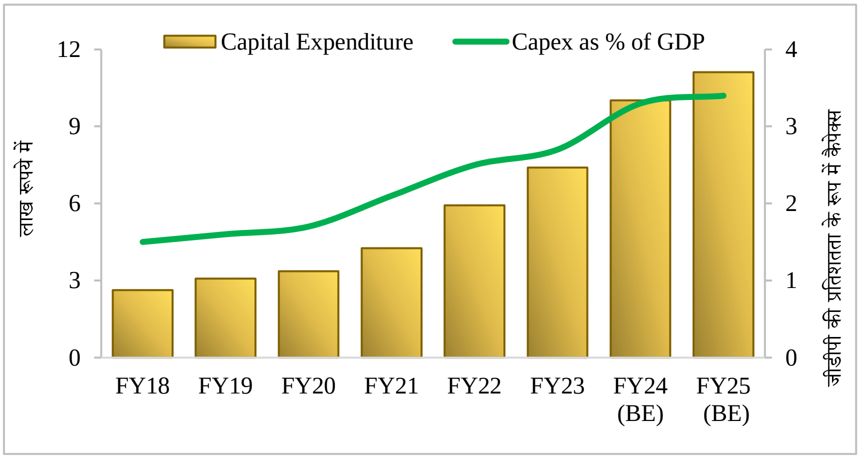

एफडीआई के अंतर्प्रवाह को दुगुना करना

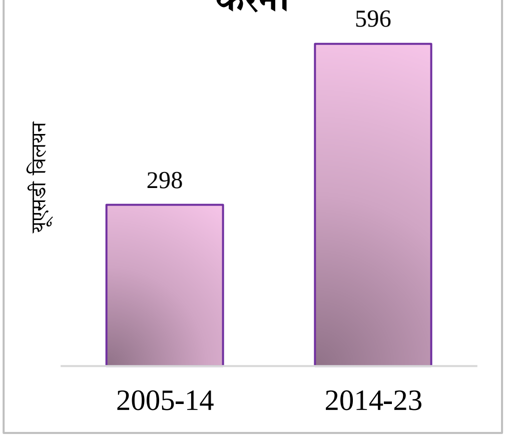

भौतिक अवसंरचना में सुधार

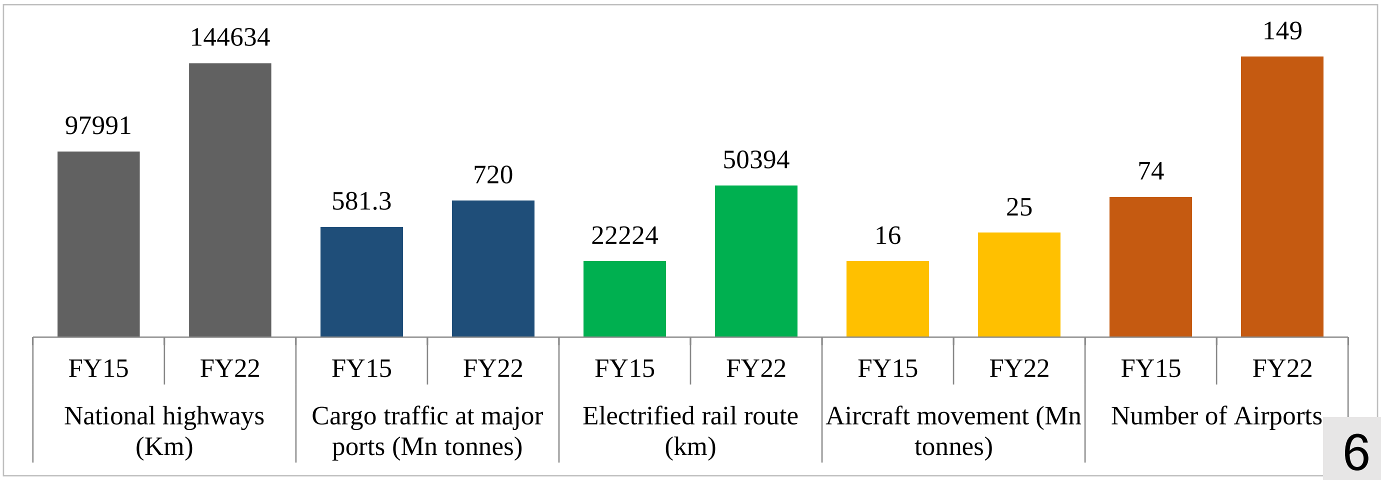

समावेशी विकास (1/2)

रोजगार सृजन सहित तेजी से विकास में राज्यों को सहायता करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम

आकांक्षी जिलों में समावेशी विकास (112)

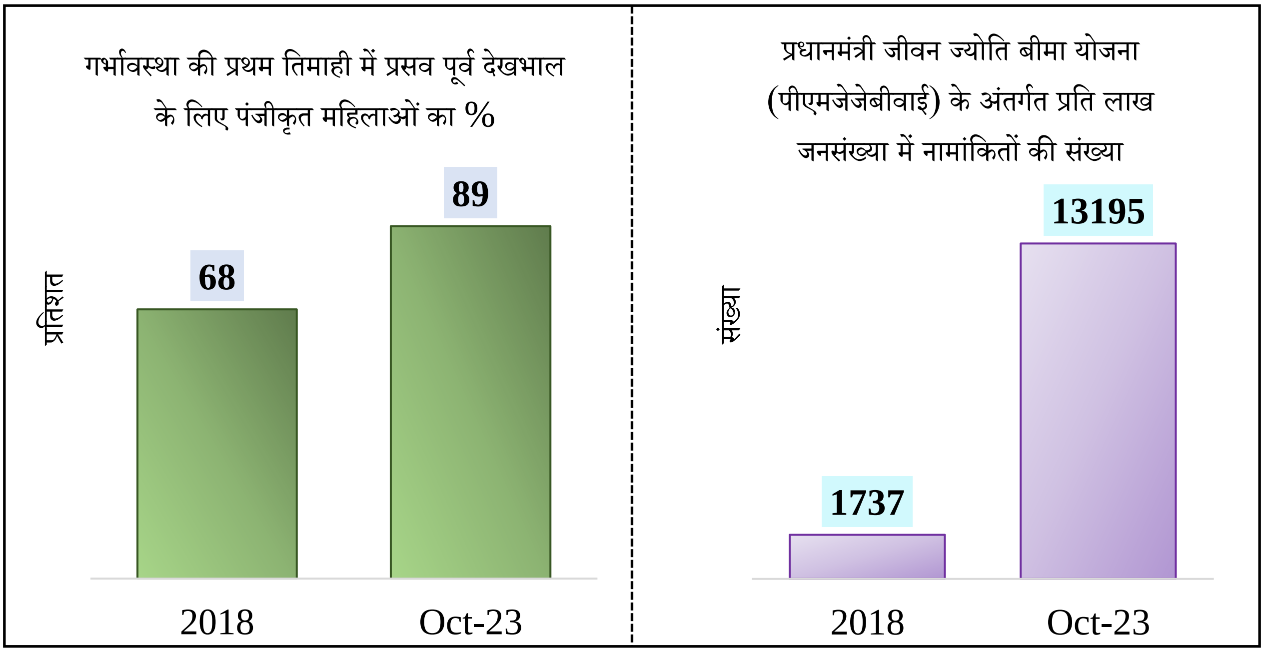

स्वास्थ्य

बालिकाओं (9-14 वर्ष) को सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना

बेहतर पोषण उपलब्धता, बचपन में आरंभिक देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 में तेजी लाई जाएगी

मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयास के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म आरंभ किया जाएगा

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशाकर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा

अमृत काल के लिए कार्यनीति (4/5)

समावेशी विकास (2/2)

आवासन

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है, अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवास का लक्ष्य

अपना घर खरीदने/बनाने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यम वर्ग आवास योजना आरंभ की जाएगी

पीएमएवाई के लिए अधिक आवंटन

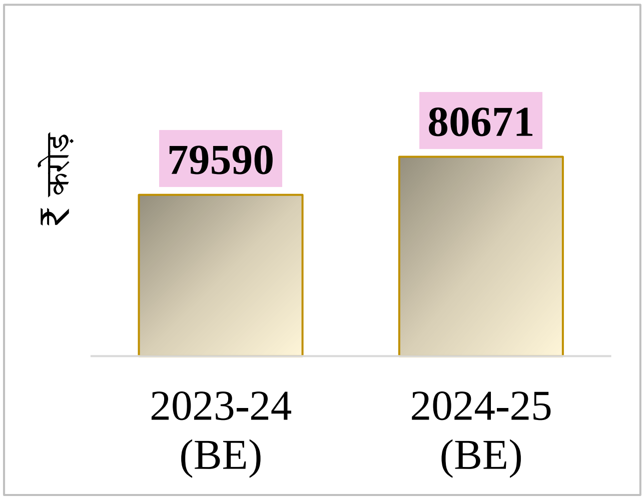

पर्यटन

कारोबार को आकर्षित करने तथा स्थानीय उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा

60 स्थानों पर जी20 की बैठकें करके वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता दिखाई गई

विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे

लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में पत्तन कनेक्टिविटी, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी

अमृत काल के लिए कार्यनीति (5/5)

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण

सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी

नैनो-डीएपी का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा

आत्मनिर्भर तिलहन अभियान- तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु कार्यनीति तैयार की जाएगी

डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा

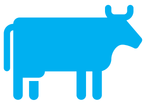

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का विस्तार ताकि जल कृषि उत्पादकता, दोहरे निर्यात और रोजगार के पर्याप्त अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके

5 एकीकृत एक्वापार्क स्थापित करना

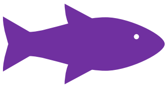

नीली क्रांति के लिए अधिक आवंटन

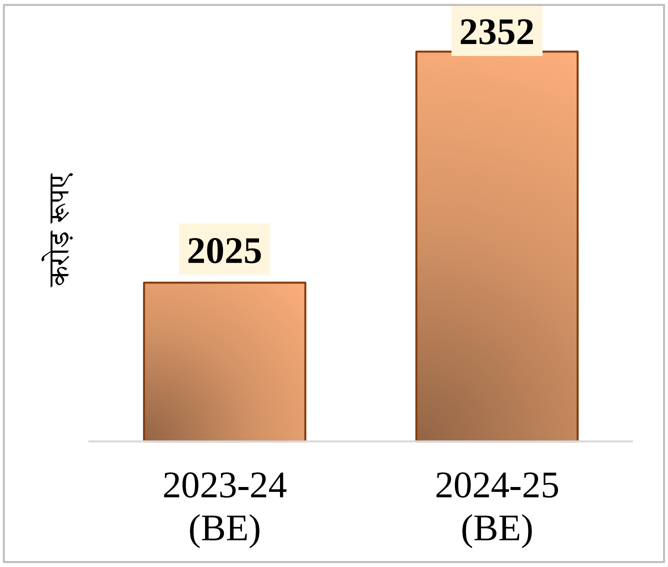

पीएम-सुक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास योजना के लिए अधिक आवंटन

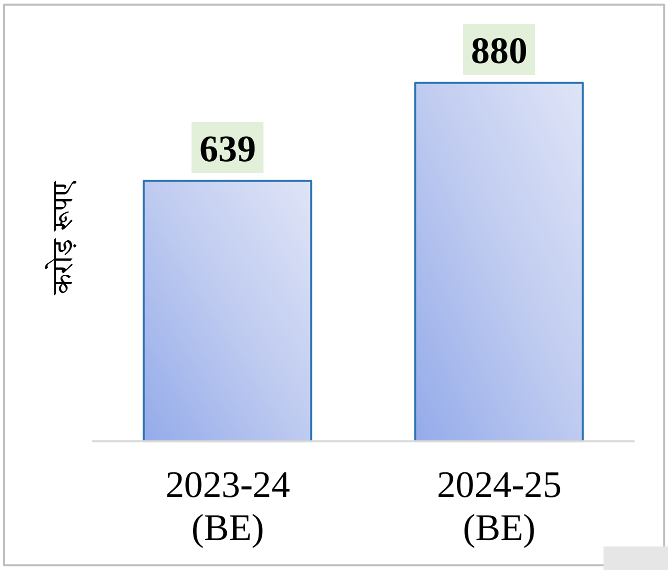

भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीला निष्पादन

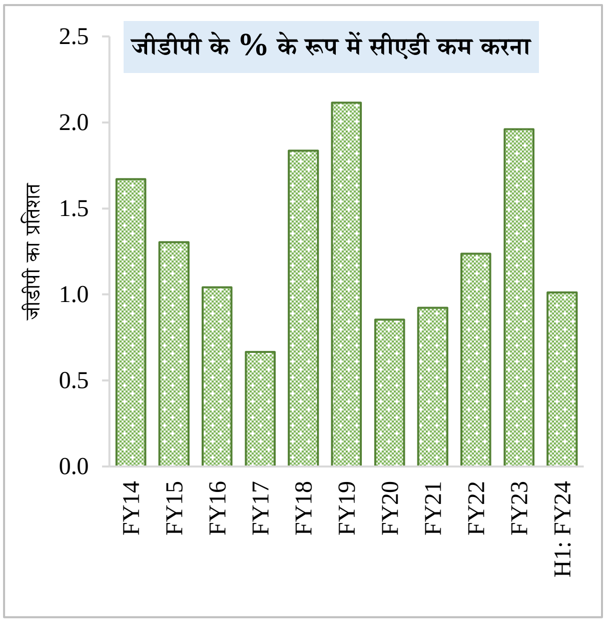

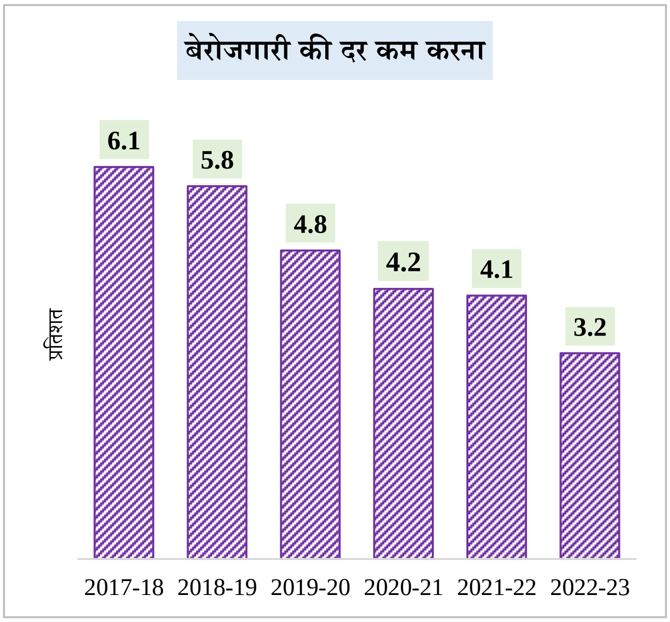

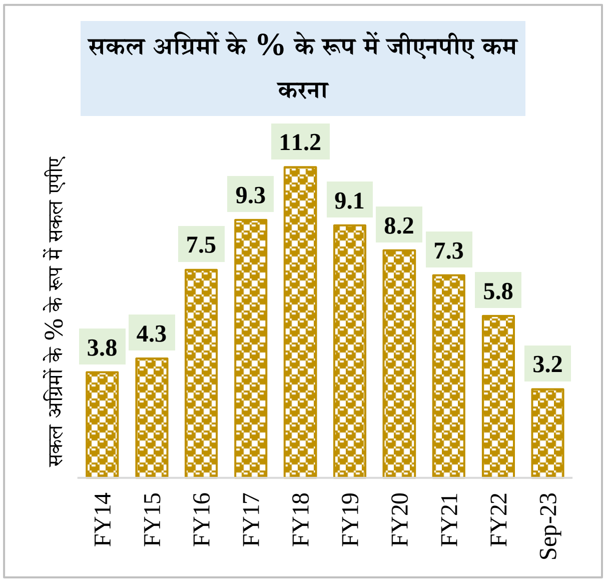

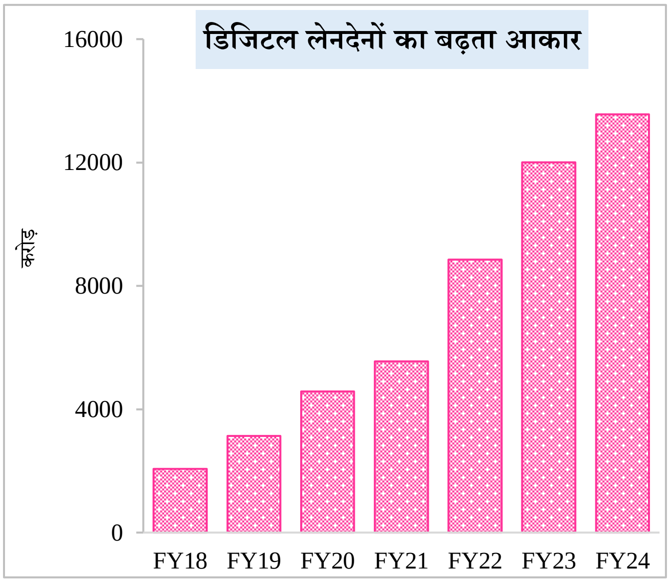

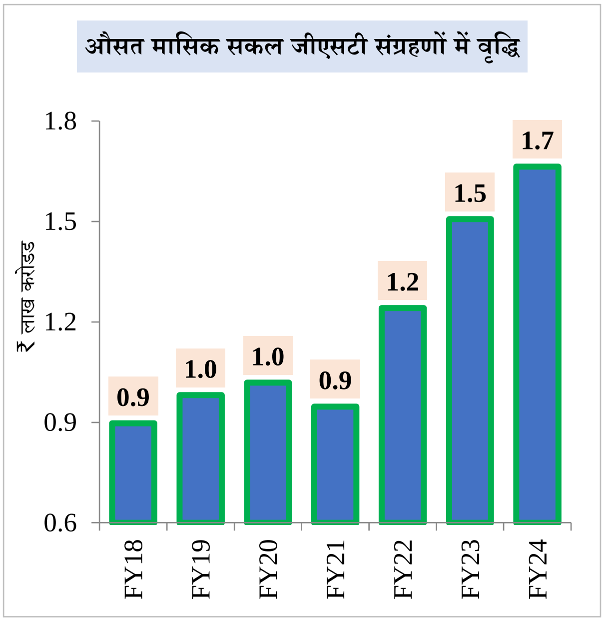

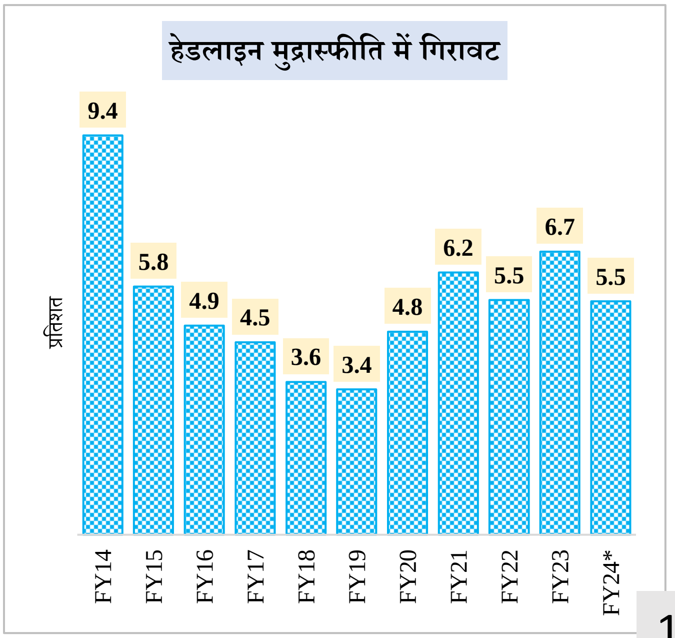

कराधान सुधारों की उपलब्धियां

प्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले 10 वर्षों में तीन गुणा से अधिक वृद्धि

विवरण दाखिलकर्ताओं की संख्या 2.4 गुणा बढ़ी

तेज रिफंड (प्रतिदाय/धन वापसी): विवरणियों के औसत संसाधन समय 93 दिवस (2013-14) से कम होकर 10 दिवस रह गया

औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रहण वित्त वर्ष 2024 में दोगुणा बढ़ कर ₹1.66 लाख करोड़ हो गया

राज्य राजस्व की कर बॉयंसी 0.72 (2012-16) से बढ़कर जीएसटी के बाद की अवधि में (2017-23) में 1.22 हो गई है

उपभोक्ताओं को हितलाभ: रसद लागत और अधिकांश वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में कमी

जीएसटी के बारे में सकारात्मक भावना

- 94% उद्योग पट्टाकर्ता जीएसटी में पारगमन को मोटे तौर पर सकारात्मक मानते हैं
- 80% प्रत्युत्तर दाता महसूस करते हैं कि जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला इष्टतमीकरण हुआ है

(अग्रणी परामर्शदात्री फर्म द्वारा संचालित सर्वेक्षण के अनुसार)

वर्ष 2019 में आयात निर्गम समय में गिरावट: -

- इन्लैंड कंटेनर डिपो में 47 प्रतिशत
- एयर कार्गो परिसरों में 28 प्रतिशत
- बंदरगाहों में 27 प्रतिशत

कर प्रस्ताव

कराधान में निरंतरता: स्टार्ट-अप और सार्वजनिक संपदा निधियों/पेंशन निधियों द्वारा किए गए निवेशों में कतिपय करहित लाभ, दिनांक 31.03.2024 को पूर्व में कालातित हो रहे कुछ आईएफएससी यूनिटों को दी जा रही कर छूटों में 31.03.2025 तक बढ़ाया गया

बकाया प्रत्यक्ष कर मांग से छूट: -

- वित्त वर्ष 10 तक के बकायों में ₹25,000 तक छूट
- वित्त वर्ष 11 से वित्त वर्ष 15 तक के लिए ₹10,000 तक

एक करोड़ करदाताओं को लाभ होने की आशा है

पुराने कर दरों को बनाए रखा गया है: -

- आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर
- मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर -22% और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15%
- नई कर व्यवस्था के अंतर्गत ₹7 लाख रूपए तक की आय वाले करदाताओं की कोई कर देयता नहीं

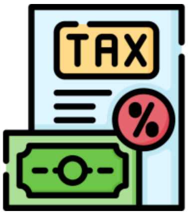

रूपया कहां से आता है

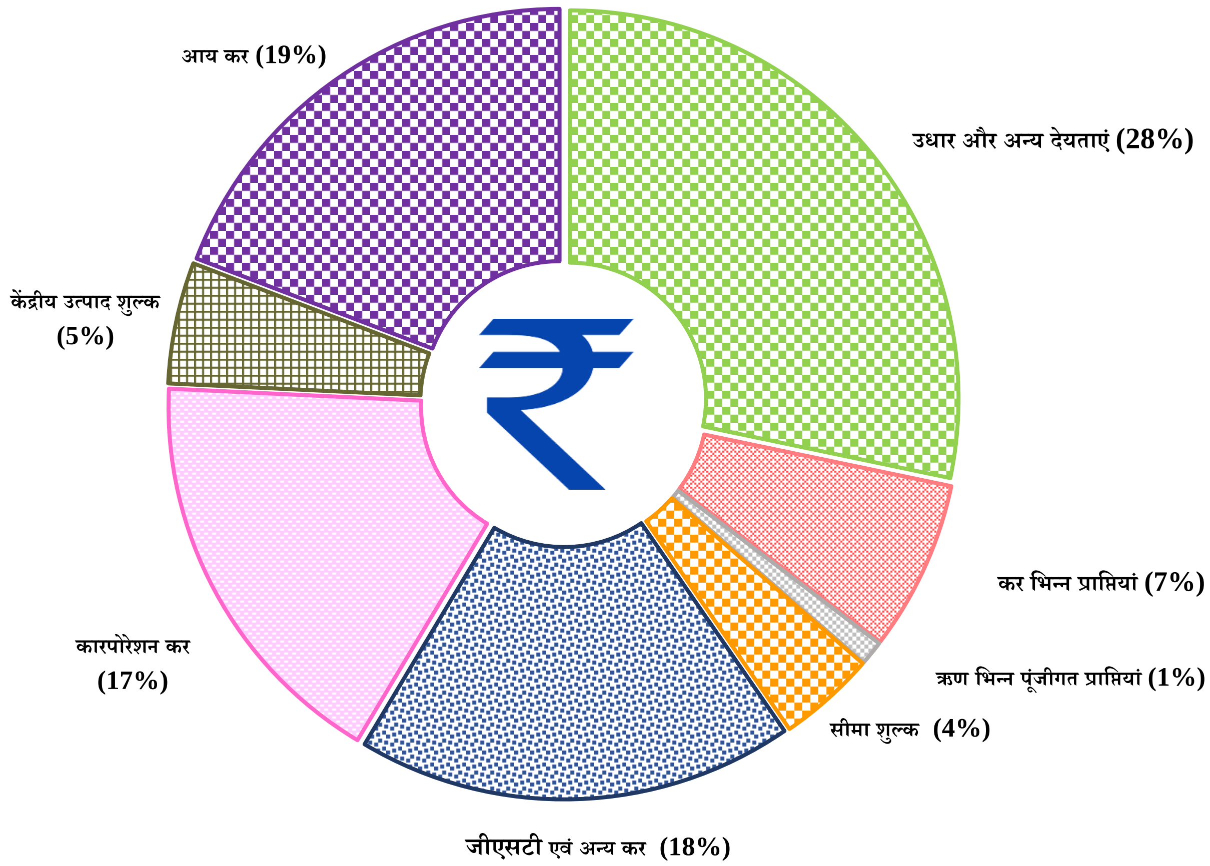

रूपया कहां जाता है

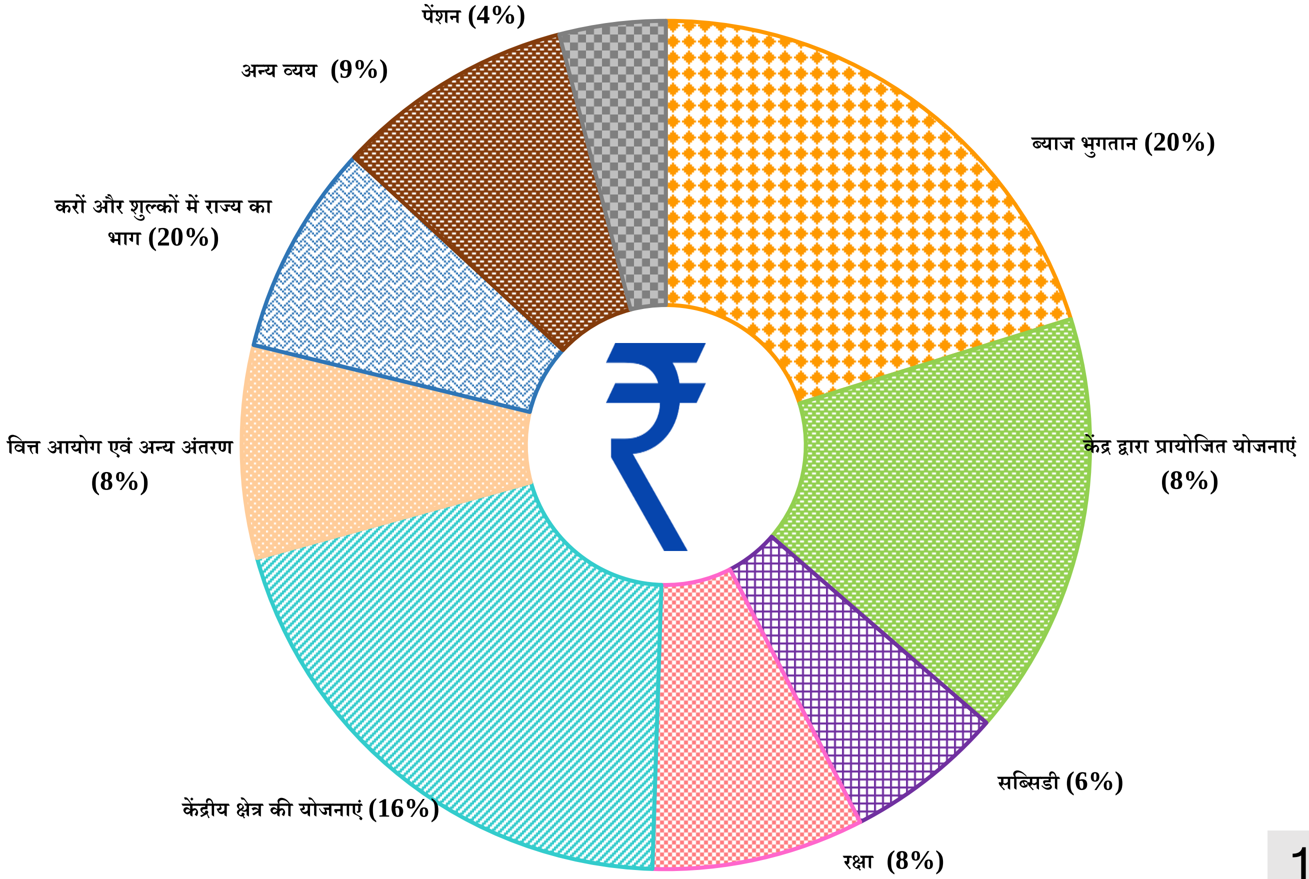

विशिष्ट मंत्रालयों को आवंटन

₹लाख करोड़ में

मंत्रालय	आवंटन
रक्षा मंत्रालय	6.2
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2.78
रेल मंत्रालय	2.55
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	2.13
गृह मंत्रालय	2.03
ग्रामीण विकास मंत्रालय	1.77
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	1.68
संचार मंत्रालय	1.37
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	1.27

प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन (₹ करोड़ में)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2023-24(ब.अ.)	2024-25(ब.अ.)
60,000	86,000

आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई

2023-24(ब.अ.)	2024-25(ब.अ.)
7,200	7,500

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना

2023-24(ब.अ.)	2024-25(ब.अ.)
4,645	6,200

सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण पारितंत्र के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम

2023-24(ब.अ.)	2024-25(ब.अ.)
3,000	6,903

सौर ऊर्जा (ग्रिड)

2023-24(ब.अ.)	2024-25(ब.अ.)
4,970	8,500

राष्ट्रीय हरित हाईड्रोजन मिशन

2023-24(ब.अ.)	2024-25(ब.अ.)
297	600

प्राप्तियां और व्यय

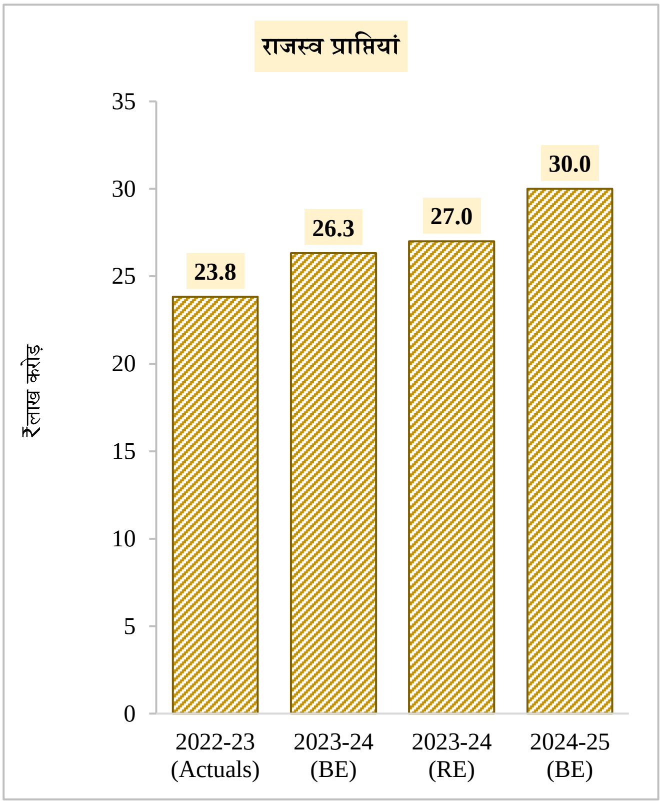

राजस्व प्राप्तियां
₹लाख करोड़
35
30
25
20
15
10
5
0
23.8
26.3
27.0
30.0
2022-23 (Actuals)
2023-24 (BE)
2023-24 (RE)
2024-25 (BE)

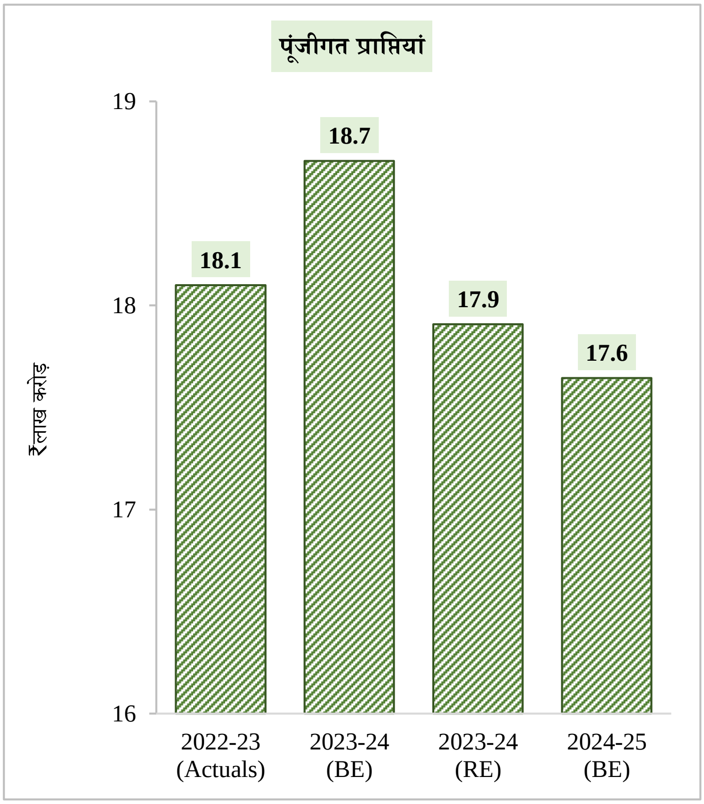

पूंजीगत प्राप्तियां
₹लाख करोड़
19
18
17
16
18.1
18.7
17.9
17.6
2022-23 (Actuals)
2023-24 (BE)
2023-24 (RE)
2024-25 (BE)

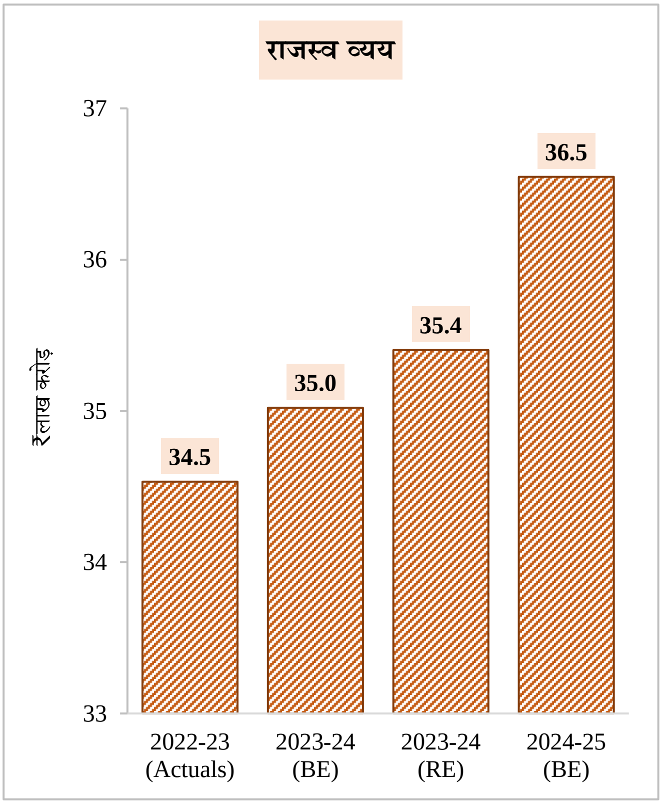

राजस्व व्यय
₹लाख करोड़
37
36
35
34
33
34.5
35.0
35.4
36.5
2022-23 (Actuals)
2023-24 (BE)
2023-24 (RE)
2024-25 (BE)

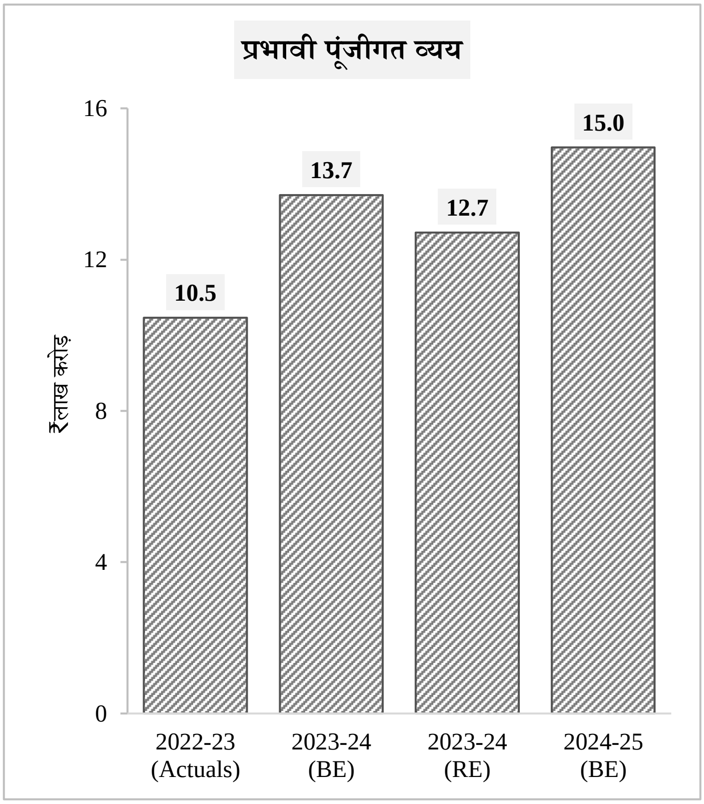

प्रभावी पूंजीगत व्यय
₹लाख करोड़
16
12
8
4
0
10.5
13.7
12.7
15.0
2022-23 (Actuals)
2023-24 (BE)
2023-24 (RE)
2024-25 (BE)